भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 3775
उत्तर देने की तारीख 09 अगस्त, 2017

5जी स्पेक्ट्रम

3775. डॉ0 उदित राज:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संपूर्ण देश में 5जी नेटवर्क/सेवाओं को शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2022 तक उक्त सेवाओं के अंतर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या को शामिल करने की संभावना है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त नेटवर्क/सेवाओं के सम्पूर्ण देश में कब तक वाणिज्यिक रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार का स्पेक्ट्रम की बोली वार्षिक आधार पर कराने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबसंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्य मंत्री
(श्री मनोज सिन्हा)

(क) और (ख) वर्ष 2012 से लेकर अब तक विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंडों में कई नीलामियों का आयोजन किया गया है। नीलाम किए गए सभी स्पेक्ट्रम "उदारीकृत स्पेक्ट्रम" हैं। इस उदारीकृत स्पेक्ट्रम का उपयोग करके दूरसंचार सेवा प्रदाता लाइसेंस के दायरे के अंदर 5जी सहित किसी भी प्रौद्योगिकी को तैनात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसी भी देश में 5जी सेवाओं का वाणिज्यिक रूप से रॉल आउट नहीं किया गया है। पूरे देश में इन सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से रॉल आउट करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

(घ) इस समय, सरकार का स्पेक्ट्रम की बोली वार्षिक आधार पर कराने की कोई योजना नहीं है। उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंडों में वर्ष 2012 से लेकर प्रति वर्ष स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की जाती रही है। अक्तूबर, 2016 में की गई नीलामी के माध्यम से विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 2354.75 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में से 964.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा था। इसके पश्चात, स्पेक्ट्रम की कमी संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****